



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 2017/चैत्र 9, 1939

No. 126]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 2017/CHAITRA 9, 1939

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2017

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रैसेबल प्रणालियां) टैरिफ (संशोधन) आदेश, 2017

(2017 का 2)

**फा.सं. 1-2/2017-बीएडंसीएस.**—भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना संख्या 39 के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, —

- (ए) जो उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (डी) और धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (के) के परंतुक के तहत केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई, और
- (बी) दिनांक 9 जनवरी, 2004 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एस.ओ. 44 (ई) और 45 (ई) के तहत प्रकाशित हुआ, —

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रैसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2017 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है, नामतः—

1. (1). इस आदेश को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रैसेबल प्रणालियां) टैरिफ (संशोधन) आदेश, 2017 (2017 का 2) कहा जाएगा।  
(2). यह आदेश इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रैसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2017 (जिसे इससे आगे मूल टैरिफ आदेश कहा गया है) के खंड 1 में, उप-खंड (3) के मद (ख) के लिए, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित किया जायेंगे, नामतः—  
““(ख) इस आदेश का खंड 3 इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के साठ दिन के बाद लागू होगा;  
(ग) इस आदेश के खंड 6 और 8 इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के तीस दिन के बाद लागू होंगे।”
3. मूल टैरिफ आदेश के खंड 10 के उप-खंड (2) में, कोष्ठक एवं शब्द “द्वितीय” के लिए, कोष्ठक एवं शब्द “चौथा” प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

सुधीर गुप्ता, सचिव, भादूविप्रा

[विज्ञापन III/4/असा./498/16]

**नोट 1**—दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2017 (2017का 1) को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—III, के खंड 4 में अधिसूचना संख्या: 21-1/2016-बीएण्डसीएसए दिनांक 3 मार्च, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था।

**नोट 2**—इस आदेश के साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम्स) टैरिफ (संशोधन) आदेश, 2017 के उद्देश्यों एवं कारणों की व्याख्या की गई है।

**अनुबंध**

#### व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. सब्सक्राइबर्स को संपूर्ण भारत में एड्रेसेबल प्रणालियों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई टेलीविजन से संबंधित प्रसारण सेवाओं के लिये टैरिफ ढॉचे हेतु भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् प्राधिकरण के नाम से जाना जायेगा) ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2017 को दिनांक 3 मार्च, 2017 को अधिसूचित किया था। मूल टैरिफ आदेश का खंड 3 इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के तीस दिन के बाद लागू होने वाला था।
2. भादूविप्रा को कुछ हितधारकों से प्रतिवेदन प्राप्त हुये जिसमे यह कहा गया कि मूल टैरिफ आदेश के खंड 1 के उप-खंड (3) का अनुभाग (ख) यह नियत करता है कि खंड 3, जो प्रसारकों को चैनलों के स्वरूप तथा अधिकतम खुदरा मूल्य की घोषणा करने के लिये अधिदेश देता है, इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के तीस दिन के बाद लागू होगा। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी तरफ दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 के विनियम 7(1) के अनुसार प्रत्येक प्रसारक को इन विनियमों के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के साठ दिन के भीतर अपना आरआईओ प्रकाशित करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि प्रसारक अपने चैनलों के स्वरूप तथा अधिकतम खुदरा मूल्य की घोषणा कहाँ करेंगे क्योंकि आरआईओ को साठ दिन के भीतर प्रकाशित करना होगा। उन्होंने प्राधिकरण से चैनलों के स्वरूप तथा अधिकतम खुदरा मूल्य की केवल घोषणा, तथा आरआईओ के प्रकाशन को लागू करने की अधिसूचि में अस्पष्टता को दूर करने का निवेदन किया है।
3. उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुये तथा मूल टैरिफ आदेश के खंड 3 तथा दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 के विनियम 7(1) को लागू करने की तिथियों से संबंधित प्रावधानों में समरूपता लाने के लिये भादूविप्रा ने मूल टैरिफ आदेश के खंड 3 को लागू करने की तिथियों को पुनर्निर्धारित करने का निर्णय किया है।
4. इसके अतिरिक्त, मूल टैरिफ आदेश के खंड 10 के उपखंड (2) में दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल सिस्टम्स) टैरिफ आदेश, 2010 को टाइपोग्राफिकल गलती के कारण दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) (एड्रेसेबल सिस्टम्स) टैरिफ आदेश, 2010 लिखा गया। इस गलती को ठीक किया गया है।
5. तदनुसार, मूल टैरिफ आदेश के खंड 1 के उप-खंड (3) तथा खंड 10 के उप-खंड (2) को संशोधित किया गया है।

## TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2017

#### THE TELECOMMUNICATION (BROADCASTING AND CABLE) SERVICES

#### (EIGHTH) (ADDRESSABLE SYSTEMS) TARIFF (AMENDMENT) ORDER, 2017

(No. 2 of 2017)

**F. No. 1-2/2017-B&CS.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Central Government, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunications), No. 39 , ----

- (a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government by proviso to clause (k) of sub-section (1) of section 2 and clause (d) of sub-section (1) of section 11 of the said Act, and
- (b) published under notification No. S.O. 44 (E) and 45 (E) dated 9<sup>th</sup> January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,----

the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order to amend the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2017, namely:-

1. (1) This Order may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff (Amendment) Order, 2017 (2 of 2017).
- (2) This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In sub-clause (3) of clause 1 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2017 (hereinafter referred to as the principal Tariff Order), for item (b), the following items shall be substituted, namely:---

“(b) clause 3 of this Order shall come into force after sixty days from the date of its publication in the Official Gazette;

(c) clauses 6 and 8 of this Order shall come into force after thirty days from the date of its publication in the Official Gazette. ”

3. In sub-clause (2) of clause 10 of the principal Tariff Order, for the bracket and word “Second”, the bracket and word “Fourth” shall be substituted.

SUDHIR GUPTA, Secy, TRAI

[ADVT III/4/Exty./498/16]

**Note 1:**The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2017 (1 of 2017) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification No. 21-1/2016-B&CS dated 3rd March, 2017.

**Note2:**The Explanatory Memorandum annexed to this Order explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff (Amendment) Order, 2017.

### Annexure

#### **EXPLNATORY MEMORANDUM**

1. The Telecom Regulatory Authority of India issued the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2017 on 3<sup>rd</sup> March, 2017 to provide the tariff framework applicable to broadcasting services relating to television provided to subscribers, through addressable systems, throughout the territory of India. Clause 3 of the principal Tariff Order was required to be implemented after thirty days from the date of its publication in the Official Gazette.
2. TRAI received representations from some stakeholders wherein it is mentioned that section (b) of sub-clause (3) of clause 1 of the principal Tariff Order stipulates that clause 3, which mandates that broadcasters have to declare the nature and MRP of pay channels, will come into effect after 30 days from the date of publication of this Order in the Official Gazette. They have also mentioned that on the other hand as per Regulation 7(1) of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Addressable Systems) Interconnection Regulations, 2017, every broadcaster has to publish its RIO within 60 days from the date of publication of these regulations in the Official Gazette. They have further mentioned that it is not clear where will broadcasters declare the nature and rates of channels as RIOs are required to be published within 60 days. They have requested the Authority to remove the ambiguity with regards to schedule for declaration of nature and MRP of pay channels; and publishing of RIO.
3. Having considered the above mentioned facts and in order to harmonize the provisions relating to implementation of the clause 3 of the principal Tariff Order and regulation 7(1) of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Addressable Systems) Interconnection Regulations, 2017, TRAI has found it necessary to re-determine the dates for implementation of the clause 3 of the principal Tariff Order.
4. In addition, in sub-clause (2) of clause 10 of the principal Tariff Order, the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2010 has been mentioned as the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (second) (Addressable Systems) Tariff Order, 2010 due to typographical error. The same error has been corrected.
5. Accordingly, sub-clause (3) of clause 1 and sub-clause (2) of clause 10 of the principal Tariff Order dated the 3<sup>rd</sup> March, 2017 have been amended.